

the plant has been cleared by the C. G. Committee.

2. In all the four cases, the import of the plant is subject to the condition that its good maintenance, useful life and reasonable value are certified by internationally reputed assessors and chartered engineers.

नेपाल के साथ व्यापार

1364. श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार में सतत कमी आई है, यदि हां, तो नेपाल की मंडियों में कुछ देशों के बड़े पैमाने पर प्रविष्ट होने के कारण कहां तक ऐसा हुआ है; और

(ख) उस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

TRADE WITH NEPAL

1364. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a steady decline in the overall trade with Nepal, if so, how far it is attributable to the fact that certain foreign countries have entered the Nepalese markets in a big way; and

(b) the steps taken by Government to increase trade with that country ?]

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपसत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नेपाल के साथ भारत का व्यापार 1965-66 में 27.15 करोड़ रु० था जो बढ़कर 1969-70 में 41.68 करोड़ रु० का हो गया था। 1970-71 में यह घट कर 33.63 करोड़ रु० का रह गया, परन्तु इसमें फिर से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी है तथा यह अप्रैल 1970 जनवरी 1971 में 30.55 करोड़ रु० की तुलना में अप्रैल 1971 जनवरी

1972 की अवधि में 31.43 करोड़ रु० का हो गया।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b) India's trade with Nepal increased from Rs. 27.15 crores in 1965-66 to Rs. 41.68 crores in 1969-70. It declined to Rs. 33.63 crores in 1970-71 but it has shown an upward trend again from Rs. 30.55 crores in April 1970-January 1971 to Rs. 31.43 crores in the corresponding period April 1971-January 1972.]

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की अधिकारिता

1365. श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हरियाणा तथा पंजाब के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय होने के कारण हरियाणा के लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार हरियाणा को दिल्ली उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश को पंजाब उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत लाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

JURISDICTION OF PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

1365. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that people of Haryana are put to a lot of trouble due to a joint High Court for Haryana and Punjab;

(b) whether Government propose to bring Haryana under the jurisdiction of the Delhi High Court and Himachal Pradesh under the High Court of Punjab; and

(c) if not the reasons therefor ?]